International Journal of Applied Research 2023; 9(4): 228-230

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2023; 9(4): 228-230
www.allresearchjournal.com
Received: 08-03-2023
Accepted: 17-04-2023

कमलेश शर्मा
सहायक आचार्य (लोक प्रशासन), राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन, पाली, राजस्थान, भारत

कृष्ण कुमार शर्मा
सहायक आचाय (संस्कृत), राजकीय महाविद्यालय, भादरा, हनुमानगढ, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
कमलेश शर्मा
सहायक आचार्य (लोक प्रशासन), राजकीय महाविद्यालय, मारवाड़ जंक्शन, पाली, राजस्थान, भारत

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : बदलाव की सार्थक पहल

कमलेश शर्मा और कृष्ण कुमार शर्मा

सारांश
ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लाभों का अवसर उठाने और भारत को पुनः विश्व गुरू की प्रतिष्ठा दिलवाने के लिए स्वतन्त्रता के उपरान्त शिक्षा नीति 1968, 1986 के क्रम में नवीन शिक्षा नीति 2020 का दस्तावेज निश्चित तौर पर प्रभावी, सार्थक एवं अनिवार्य पहल है। के. कस्तूरीरगंन की अध्यक्षता में प्रस्तुत NEP 2020 परिवर्तन व सुधार की क्रांतिकारी तैयारी है जिसमें गुणवता वृद्वि, शोध व नवाचार संस्कृति पर ध्यान केन्द्रण के साथ–साथ सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा पर निवेश करने का संकल्प लिया गया है ताकि कुशल मानवीय संसाधन की प्राप्ति हेतु दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा वृहद् पैमाने पर निवेश को परिणाम प्रतिफल में परिणित किया जा सकें। अतीत से सीखकर वर्तमान में भविष्य की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रणालीगत कमियों का उन्मूलन राज्य सरकारों व निजी क्षेत्र से बेहतर समन्वय करके संविधान में उल्लेखित आदर्शों मूल अधिकारों मूल कर्तव्यो की स्थापना द्वारा समावेशी, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था निर्मित करके सतत, संतुलित व धारणीय विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। NEP 2020 विद्यालयीय शिक्षा व उच्च शिक्षा में व्यापक सुधारों, परिवर्तनो का दस्तावेज है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के साथ मानविकी कला व सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान का समन्वय करके मानवाधिकारों की रक्षा, प्रदूषण, जलवायु–परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबन्धन[1], रोजगार, जैसे मुद्दों का हल करने की सामर्थ्य विकास का उपक्रम है। किस सीमा तक NEP 2020 के लक्ष्य प्राप्य होंगे यह हमारे विचार, कार्य संस्कृति व दृष्टिकोण बदलाव पर निर्भर है।

कूटशब्द : ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, शोध व नवाचार संस्कृति, समावेशी–न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, धारणीय विकास, सकल घरेलू उत्पाद

प्रस्तावना
NEP 2020 इक्कीसवीं शताब्दी में भारत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उठाया गया क्रांतिकारी कदम है जिसमें विद्यालयी शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा में कई सुधारात्मक परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है। जिससे वैश्वीकरण के दौर में वसुधैव कुटुम्बकम् की अवधारणा का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान–विज्ञान की एकाधिकारवादी सीमाएं हटाकर वैश्विक अनुसंधान, आविष्कार का भारतीय युवाओं के हित में सदुपयोग किया जा सके। यह तो समय के गर्भ में है कि इतने व्यापक स्तर पर आरोपित प्रयासों की परिणामोन्मुखी प्रभावकारी समयकालिक आयामों के साथ कैसे सन्तुलन बैठाना है और किस सीमा तक सफल होंगे। राजनीतिक दांवपेच, संवैधानिक प्रावधानों, नेतृत्व की इच्छा शक्ति, नौकरशाही की कार्य संस्कृति, परिवर्तन के प्रति अनिच्छापूर्ण व्यवहार का इतिहास, वित्त की समुचित व्यवस्था से कैसे निपटना है और हितधारकों व क्रियान्वयन इकाइयों के दृष्टिकोण में परिवर्तन किस सीमा तक कर पाएंगे, इसी बिन्दु पर NEP 2020 की सफलता निर्भर है। NEP 2020 के नीति दस्तावेज से परिलक्षित होता है कि परीक्षा का तनाव, बाल केन्द्रित शिक्षा अन्तःअनुशासनात्मक अध्ययन, शोध व नवाचार पर केन्द्रण, वैश्विक विश्वविद्यालयों के परिसरो की स्थापना, रोजगारपरक शिक्षा हेतु कौशल विकास कार्यक्रम, श्रम की महता, दूरस्थ शिक्षा, खुला विश्वविद्यालय प्रारूप, बजटीय आवंटन में वृद्वि का निर्णय, मातृभाषा संरक्षण लोक कला, हस्तशिल्प पर ध्यान देना, बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी व्यवस्था, वंचित वर्गो अजा, अजजा, अल्पसंख्यको, महिला, निर्धन वर्गो तक सर्वसुलभ शिक्षा की पहुच जैसे विषयों को केन्द्रीय भूमिका प्रदान की गई है। आरम्भ उत्तम है तो परिणाम भी सर्वोतम ही होगे जिससे भारत एक बार पुनः प्राचीन ज्ञान–कौशल की प्रतिष्ठा व विश्व गुरू के पद पर सुशोभित हो पाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं : नवीन पहल
के.कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में NEP 2020 का दस्तावेज तैयार किया गया जिसे केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 29 जुलाई 2020 को अनुमोदित किया गया।

इसमें प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक अनेको सुधारों की पहल की गई है ताकि शहरी व ग्रामीण भारत को जीडीपी के 6 प्रतिशत निवेश[2] द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु व्यावसायिक कौशल, ज्ञान, अभिरूचि, शोध, नवाचार जैसे प्रत्येक मानक पर सर्वश्रेष्ठ बनाया जा सके।

विद्यालयी शिक्षा प्रतिरूप का नवीन प्रारूप

वर्तमान शिक्षा प्रणाली 10+2 प्रतिरूप पर आधारित है जिसे 5+3+3+4 प्रतिरूप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा[3]। इस नीति दस्तावेज में विद्यालयी शिक्षा में आंगनबाड़ी/प्री–प्राइमरी पर विशेष ध्यान दिया गया है। ECCE (Early Childhood Caare and education) पर ध्यान देने से जहां पूर्ववर्ती व्यवस्था में 6 वर्ष की आयु में विद्यार्थी शाला में प्रविष्ट होता था अब 3 वर्ष की आयु से ही उसको शिक्षा जगत से जोडा जाएगा।

नवीन प्रारूप	कक्षा स्तर	आयु वर्ग	चरण
5	आंगनबाडी नर्सरी/प्री–प्राइमरी	3–6 वर्ष	फाउण्डेशन स्टेज
		6–8 वर्ष	फाउण्डेशन स्टेज
3	कक्षा 3–5	8–11 वर्ष	प्राथमिक शिक्षा
3	कक्षा 6–8	11–14 वर्ष	मध्यम स्तर
4	कक्षा 9–12	14–18 वर्ष	अंतिम स्तर

विशिष्ट वर्गो पर ध्यान केन्द्रण

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के विद्यार्थियों को विद्यालय से सम्बद्व करने के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण पर बल देते हुए छात्रवृत्ति योजना विस्तार, निदानात्मक शिक्षण, छात्रावासों की व्यवस्था, पर्याप्त दक्ष शिक्षको की व्यवस्था करने पर ध्यान दिया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए शैक्षणिक रूप से सशक्त करने की रणनीति पर कार्य किया जा रहा है जिससे हाशिए पर पड़े वर्गो का सशक्तीकरण किया जा सके।

बोर्ड परीक्षा तनाव रहित बनाने की कवायद

पूर्ववर्ती शिक्षा प्रणाली में विषय चुनाव सैकण्डरी बोर्ड परीक्षा के बाद किया जाता था परन्तु NEP 2020 में कक्षा 9 में ही विषय चुनाव का प्रावधान है। परीक्षा का तनाव कम करने, रटन्त विद्या की जगह सतत अध्ययन प्रोत्साहन के लिए सेमेस्टर प्रणाली लागू करके वर्ष में दो बार परीक्षाओ का आयोजन ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव आधार पर किया जाएगा।

उच्च शिक्षा में परिवर्तन व सुधारात्मक उपाय

10+2+3 प्रणाली के वर्तमान स्वरूप में तीन वर्षीय स्नातक की पढाई मध्य में छोड़ने पर छात्रो को कोई लाभ नहीं होता था परन्तु NEP 2020 में इस समस्या पर विचार किया गया है।

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केन्द्र बनाने के शोध संस्कृति पर विशेष बल दिया गया है और इन्हे बहुविषयक संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें एक वर्ष की पढाई पर सर्टिफिकेट, दो वर्ष की पढाई पर डिप्लोमा और तीन वर्ष की पढाई पर डिग्री प्रदान करने की व्यवस्था लागू की गई है ताकि कोई भी विद्यार्थी इन संस्थानों में प्रविष्ट हो वह खाली हाथ ना लौटे। इसी क्रम में 5 वर्ष का सयुंक्त ग्रेजुएट मास्टर कोर्स नवीन विचार है।

इसमें विशेषज्ञता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और उच्च शिक्षा का ढांचा इसके अनुरूप पुनगर्ठन किया जाएगा। शोध संस्कृति स्थापना के लिए अधिक राशि उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया जाएगा जिससे गुणवत्ता के साथ शोधार्थियों की संख्या वृद्वि और प्रासंगिक शोध कार्यो को वरीयता दी जा सकें। 2030 तक प्रत्येक जिले या उसके समीप न्यूनतम एक वृहत् बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा[4]। नई नीति में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) के गठन का प्रस्ताव काम के अनुसार इसके चार वर्टिकल होगे– नियमन, मान्यता, फंडिग और शैक्षणिक मानक। यह UGC, । ICTE, NCTE जैसे मौजूदा नियामको का स्थान लेगा[5]।

1. NHERC (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद्)– विनियमन हेतु
2. GEC (सामान्य शिक्षा परिषद्)– मानक निर्धारण निकाय
3. HEGC (उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद्)– वित्त पोषण हेतु
4. NAAC (राष्ट्रीय मूल्याकंन एवं प्रत्यायन परिषद्)– प्रत्यायन हेतु[6]

NEP 2020 का मुख्य आकर्षण बहु विषयक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की स्थापना करना है जिससे विषयों के मध्य की खाई को पाटा जा सकें और छात्रों का बहु आयामी विकास सुनिश्चित किया जा सकें।

प्ळछव्न् (1985) को संवर्धित करके नियमित अध्ययन करने में असमर्थ विद्यार्थियों को छप्व्ै एवं राज्यों के व्चमद ैबीववसे द्वारा व्क्स् (खुला व दूरस्थ शिक्षा) कार्यक्रमों से जोडने का लक्ष्य है जिससे वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। कक्षा 3,5,8 हेतु छप्व्ै के द्वारा व्चमद स्मंतदपदह की व्यवस्था की जाएगी।

मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कला के साथ–साथ अभियांत्रिकी चिकित्सा व विज्ञान और तकनीकी का समन्वित अध्ययन द्वारा अन्तःअनुशासनात्मक शैक्षिक प्रणाली विकसित करने पर फोकस किया जा रहा है। उच्च शिक्षा में जिज्ञासुवृत्ति वाले मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करने हेतु छंजपवदंस त्मेमंतबी थ्वनदकंजपवद की स्थापना[7] की जाएगी और ज्ञानपरक समाज निर्मित किया जा सकेगा। नीति के अनुच्छेद 11.11 के अनुसार समग्र और बहुविषयक शिक्षा हेतु प्प्ड और प्प्ज् आदि की तर्ज पर बहुविषयक शिक्षा और अनुसन्धान विश्वविद्यालय ;डम्त्न्द्ध नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी[8]।

NEP 2020 द्वारा पर्याप्त शैक्षणिक स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ लचीले पाठ्यक्रम निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा है विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों के परिसर भारत में स्थापना की परिकल्पना द्वारा ज्ञान की वैश्विक साझेदारी प्रोत्साहन को सुनिश्चित किया जाएगा। ऑनलाईन एजुकेशन व डिजिटलीकरण को प्रोत्साहन भी मिलेगा। छात्राओं व ट्रांसजेण्डर वर्ग हेतु ळमदकमत प्दबसनेपवद निदक की स्थापना[9] की पहल से एक समान गुणवतापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

शिक्षको के लिए प्रावधान–NEP 2020 शिक्षको की भर्ती प्रक्रिया पादर्शिता से करने पर बल देती है और पदोन्नति प्रणाली को भी योग्यता आधारित बनाया जा रहा है। इसके लिए NPST (राष्ट्रीय पेशेवर मानक) तैयार किए जाएगे और छात्र, शिक्षक अनुपात 30:1 रखा जाएगा[10]। सामाजिक–आर्थिक रूप से वचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रो के स्कूलो में शिक्षक–विद्यार्थियों का अनुपात 25:1 से कम होगा[11]।

प्रत्येक शिक्षक अपने आपको अद्यतन करने के लिए व स्वयं के व्यावसायिक विकास हेतु स्वेच्छा से 50 धंटो के सतत व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम में भागीदारी करें[12]। निरन्तर शिक्षक समुदाय व विचारकों द्वारा मांग की जा रही थी कि शिक्षक वर्ग को गैर शैक्षणिक कार्यों से इन्हे मुक्त रखा जाए इस विषय पर NEP 2020 में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधयों से स्वतंत्र रखकर अनावश्यक तनाव व अतिभारण से बचाकर शिक्षण संस्थानों में सदुपयोग पर ध्यान केन्द्रण किया गया है साथ ही NCTE, NCERT के परामर्श पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NCFTE 2020) निर्मित की गई है। 2030 तक शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय B.Ed. न्यूनतम शर्त होगी। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद शिक्षक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा तैयार करेगी[13]।

त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय एकता की अभिवृद्वि करने वाला कदम है। भाषायी विविधता को संरक्षण प्रदान करने वाला उपाय है। NEP 2020 में अग्रेंजी, हिन्दी व स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का माध्यम रखा गया है। कक्षा पांच तक की पढाई स्थानीय/क्षेत्रीय/मातृभाषा में करवाने की पहल की गई है। अग्रेंजी की अनिवार्यता से स्वतंत्र रखा गया है। संधीय ढांचा व ऐतिहासिक अनुभवों के परिदृश्य में भाषा का चुनाव बलपूर्वक थोपा नहीं जाएगा। भारतीय संकेत भाषा को सम्पूर्ण राष्ट्र में मानकीकृत किया जायेगा[14]।

निष्कर्ष

सुधारात्मक परिवर्तनों की श्रृखंला में NEP 2020 नए भारत के निर्माण का रोडमैप है जिसमें स्वावलम्बन पर आधारित आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार करने के लिए श्रम का महत्व स्थापित करते हुए व्यावसायिक कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है। कक्षा 6–8 में पढ़ने के दौरान सभी विद्यार्थी एक 10 दिवसीय बस्ता रहित पीरियड में भागीदारी करेगे, जिसमें वे स्थानीय कला शिल्प विशेषज्ञो जैसे काष्ठ कला विषेषज्ञ (कारपेन्टर), पौध कला विशेषज्ञ (माली), मिट्टी की कला के विशेषज्ञ (कुंभकार) आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेगे। इसी तर्ज पर कक्षा 6–12 तक अवकाश के दौरान भी विभिन्न व्यावसायिक कला शिल्प समझने हेतु अवसर उपलब्ध कराये जा सकते है। ब्वकपदह सिखाने की योजना, स्थानीय व रूचि के कौशल से जुड़ाव पैदा करके हर हाथ को रोजगार सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। छात्रों की प्रगति का मूल्याकंन करने हेतु च।त।ज्ञभ एक राष्ट्रीय आकलन केन्द्र की स्थापना की गई है। पाठयक्रमों में लचीलापन रखते हुए बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी प्रणाली, एकेडमिक बैक ऑफ क्रेडिट, कॉमन एडमिशन टेस्ट द्वारा प्रवेश, नेशनल मेंटरिंग प्लान, न्छ के सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शैक्षिक गुणवत्ता बनाए रखते हुए उच्च शिक्षा में सकल नामाकंन अनुपात 2030 तक मौजूदा 26 प्रतिशत से बढाकर 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है।

लुप्तप्राय लोक कलाओं का संरक्षण एवं पुनरूद्धार की योजना, समृद्व भारतीय विविधता का पर्यटन द्वारा प्रत्यक्ष स्थायी ज्ञान प्रदान, इतिहास, कला संस्कृति का परिचय, आकांक्षी जिलों esa SEZ (स्पेशल एजुकेशन जोन) बनाना, वैश्विक संस्थानों के साथ सांस्कृतिक, बौद्विक आदान प्रदान की रणनीति बनाना जैसे कदम उठाए गए है। वस्तुतः NEP 2020 भारत की 21वीं सदी में वैश्विक मापदण्डों के अनुरूप नवीन चुनौतियों से निपटने की नीति है। शिक्षा की व्यापक, सर्वसुलभ तरीके से सभी को प्राप्ति हो ज्ञान कौशल, आत्मविश्वास में वृद्वि करके विचारों, मूल्यों, दृष्टिकोण में नवीनता लाने का सद्प्रयास है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्विमता के दौर में मशीनों का उपयोग बढ़ा है वही इस मांग–पूर्ति के अन्तर को NEP 2020 द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. विपुल सिंह, नई शिक्षा नीति/नजरिया–पर्यावरण पर नई दृष्टि जरूरी, आउटलुक हिन्दी, 24 अगस्त 2020 पृ.सं. 7
2. प्रकाश कुमार, नई शिक्षा नीति– अब दारोमदार अमल पर , आउटलुक हिन्दी, 24 अगस्त 2020 पृ.सं. 6
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 8
4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 56
5. प्रकाश कुमार, नई शिक्षा नीति– अब दारोमदार अमल पर , आउटलुक हिन्दी, 24 अगस्त 2020 पृ.सं. 6
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 76
7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 74
8. डॉ.सुधांशु कुमार पाण्डेयः शिक्षा नीति : 2020 (कु संस्तुतियाँ एवं विमर्श) पृ. 28,29
9. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पृ. 40
10. डॉ. मौसम सिन्हा, वर्षा सक्सेनाः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पृ. 27
11. डॉ.सुधांशु कुमार पाण्डेयः शिक्षा नीति : 2020 (कु संस्तुतियाँ एवं विमर्श) पृ. 80
12. डॉ. मौसम सिन्हा, वर्षा सक्सेनाः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पृ. 71
13. डॉ. मौसम सिन्हा, वर्षा सक्सेनाः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पृ. 22
14. डॉ.सुधांशु कुमार पाण्डेयः शिक्षा नीति : 2020 (कु संस्तुतियाँ एवं विमर्श) पृ. 65।